उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 07 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(02/30)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी से चारधाम ऑल वेदर रोड़ प्रोजेक्ट पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के साथ देहरादून के महापौर श्री सुनील उनियाल गामा भी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(02/29)

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरूवार को सचिवालय सभागार में विद्यालयों में उपलब्ध कराये जा रहे मध्याह्न भोजन योजना की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की 14 वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश की देयता समय पर उपलब्ध कराई जाय। उन्होंने एमडीएम संचालित विद्यालयों में नामांकित तथा औसत लाभान्वित बच्चों के अन्तर में समानता लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने एमडीएम के अन्तर्गत छात्रों को दिये जा रहे भोजन की गुणवत्ता की जांच और सघनता से करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने मध्याहन भोजन योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों द्वारा वापस की गई अनारम्भ किचन कम स्टोर की धनराशि को उपयोग में लाने के लिये विद्यालयों का पुनः परीक्षण कर सर्वशिक्षा अभियान भवन के साथ किचन कम स्टोर के निर्माण की संभावनाएं तलाशने को कहा। मुख्य सचिव ने विद्यालयों में नए प्रयोग के तौर पर आरम्भ की गई ''अपना किचन अपना भोजन'' योजना में स्वयं भी बच्चों के साथ भोजन करने तथा इस योजना का जायजा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पहल से बच्चों में सामुहिक कार्य करने की प्रकृति तथा संस्कृति के सृजन में निश्चित रूप से बल मिलेगा। मध्याहन भोजन योजना के टोल फ्री न0 पर दर्ज शिकायतों की मुख्य सचिव द्वारा समीक्षा की गई तथा आईसीडीएस में कुपोषित बच्चों को दिया जाने वाला ''ऊर्जा'' खाद्य पदार्थ जिसकी किमत 5.36 रूपए प्रति 50 ग्राम है, की आपूर्ति पर चर्चा हुई।

महानिदेशक शिक्षा सुश्री ज्योति यादव द्वारा बताया गया कि विगत 07 जून 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मध्याह्न भोजन वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2018–19 की प्रोजेक्ट अपूर्वल बोर्ड में प्रदेश द्वारा प्रस्तावित 16,932.14 लाख रूपए की योजना में 11,026.92 लाख रूपए का केन्द्रांश का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। भोजन की गुणवत्ता की प्रयोगशाला में जांच पर वर्ष 2018719 में डेढ लाख रूपए का प्राविधान किया गया है।

महानिदेशक शिक्षा द्वारा बताया गया कि प्रदेश में जिन विद्यालयों में एमडीएम संचालित है उनकी संख्या 12042 है तथा 04 लाख 22 हजार 447 बच्चों का इनमें नामांकन है और विद्यालयों में औसत उपस्थित बच्चों की संख्या 03 लाख 37 हजार 891 है। तथा कार्यरत भोजन माता 17 हजार 68 है तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत भोजन माताओं की संख्या 9456 है। । इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर के 5297 विद्यालयों में 02 लाख 99 हजार 538 बच्चों का नामांकन तथा औसत लाभान्वित बच्चे 02 लाख 40 हजार 870 है। उन्होंने बताया कि हंस फांउडेशन द्वारा प्रदेश के 5519 स्कूलों में गैस कनेक्शन तथा 4595 स्कूलों में गैस चूल्हा सहित गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं। उन्होंन यह भी बताया कि विद्यालयों में नए प्रयोग के तौर पर अपना किचन अपन भोजन योजना भी शुरू की गई है, जिसमें बच्चों के सहयोग से खाना बनाया जाता है तथा बच्चों में इससे साथ कार्य करने की संस्कृति को बल मिलता है।

इस अवसर पर सचिव शिक्षा आर. मीनाक्षी सुन्दरम, निदेशक शिक्षा डॉ. राकेश कुंवर, निदेशक रमसा सीमा जौनसारी, संयुक्त निदेशक पी के बिष्ट सहित शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–02(02/28)

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत शुक्रवार को हरिद्वार स्थित ऋषिकुल मैदान में आयोजित किये जा रहे आरोग्य मेले का शुभारम्भ करेंगे। प्रदेश के आयुष एवं आयुष चिकित्सा मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। दिनांक 08 फरवरी से 10 फरवरी, 2019 तक आयोजित होने वाला यह मेला आयुष मंत्रालय भारत सरकार, आयुष विभाग उत्तराखण्ड तथा सीआईआई के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखण्ड प्रो. अरूण कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस आरोग्य मेले में नाड़ी परीक्षण एवं दन्त निष्कासन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जायेगा। जिसमें गुजरात एवं महाराष्ट्र से मुख्य रूप से आये विशेषज्ञों द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों एवं आयुर्वेद कॉलेजों के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक के मुख्य विषयों पर जनसाधारण हेतु व्याख्यान दिया जायेगा।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 07 फरवरी, 2019 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–01(02/27)

सचिवालय सभागार में आज गुरूवार को मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ मा. प्रधानमंत्री के पन्द्रह सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य समिति की समीक्षा बैठक हुयी।

प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति कुल 42439 (नवीन 29807, रिन्यूवल 12632) छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया। निदेशालय स्तर से सत्यापन के उपरान्त कुल 22640 (नवीन 13441 रिन्यूवल 9199) छात्रों के आवेदन पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये गये तथा बढ़ाने के निर्देश दिये गये।

बैठक में अवगत कराया गया कि समस्त राजकीय पालीटैक्निकों में कुल 11287 छात्र–छात्रायें हैं, जिनमें से कुल 326 अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। एस.एस.डी.पी. योजनान्तर्गत 11 वीं पंचवर्षीय योजना में राजकीय पॉलीटैक्निक, सिडकुल (हरिद्वार) का कार्य पूर्ण तथा राजकीय पॉलीटैक्निक, सितारगंज (ऊधमसिंह नगर) निर्माणाधीन हैं, मुख्य सचिव ने अवशेष धनराशि रु 291.12 लाख भारत सरकार से स्वीकृति कराने हेतु अनुसरण करने के निर्देश दिये।

बैठक में बताया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग के बेरोजगारों हेतु स्वरोजगार योजना में वर्ष 2018–19 में 200.00 लाख रुपये राशि में से 15.956 लाख व्यय कर 32 लाभार्थियों को रोजगार दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 925 छात्रों को मुख्यमंत्री हुनर योजना में प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति 37 संस्थाओं को प्रदान की गयी है, जिस पर कुल 93.125 लाख की धनराशि व्यय किया जाना है।

मौलाना आजाद एजुकेशन फाईनेन्स फाउन्डेशन योजना में जनपदों से प्राप्त रु 96.151 लाख लागत के 36 नए प्रस्तावों की स्वीकृति की जानकारी दी गई योजना में प्रत्येक लाभार्थीयों को तकनीकी/प्राविधिक शिक्षा हेतु 5 लाख रु ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम में स्वीकृत विद्यालय, पेयजल, पम्पिंग योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिये।

बैठक में अवगत कराया गया कि वर्ष 2017–18 को राज्य में राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा–1 से 08 तक के पंजीकृत कुल 10,34,310 छात्र/छात्राओं में 1,28,596 (61,151 छात्र एवं 67,45 छात्रायें) अल्पसंख्यक छात्र/छात्रायें है। इन्हे सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क पाठय प्रस्तकें एवं मध्याहन भोजन दिया जा रहा हैं। मदरसा बोर्ड द्वारा 297 मदरसों का पंजीकरण किया जा चुका है, अल्पसंख्यक समुदायों की घनी आबादी क्षेत्रों/ग्रामों में 17 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थित है। जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की 25 छात्रायें अध्यनरत् है। आई.डी. एम.आई योजना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के स्थान पर शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित किये जाने की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई है। निदेशक मदरसा शिक्षा परिषद् द्वारा वर्तमान तक कुल 23 मदरसों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था का प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, वर्ष 2017–18 में 01 मात्र मदरसे हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि रु 19.00 लाख स्वीकृति प्रदान करते हुए केन्द्रांश की प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु 7.13 लाख द्वितीय किश्त की मांग की गई है, राशि जारी करने हेतु मुख्य सचिव ने 127.57 लाख की अवशेष द्वितीय किश्त केन्द्र से जारी कराने हेतु केन्द्र में अनुसरण करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिये।

वर्ष 2018–19 में राज्य पोषित पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना में दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक कुल 12383 छात्र–छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन को कम बताते हुए मुख्य सचिव ने तेजी लाने के निर्दश दिये। गत वर्ष में 38477 छात्र लाभान्वित हुए थे। पोस्ट– मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कुल 9100 (नवीन 7832, रिन्यूवल 1268) छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया। निदेशालय स्तर से सत्यापन के उपरान्त कुल 2916 छात्रों (नवीन 1961 रिन्यूवल 955) के आवेदन पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये गये मुख्य सचिव ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये।

बैठक का संचालन अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण डा. रणवीर सिंह ने किया। सह संचालन निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण धीरेन्द्र दत्ताल ने किया।

बैठक में अपर सचिव शहरी विकास चन्द्रेश यादव, सचिव हरबंस सिंह चुंग, आयुक्त श्रम आनंद श्रीवास्तव, अपर सचिव विद्यालयी शिक्षा रवनीत चीमा, जिलाधिकारी देहरादून एस. मुरूगेशन, सदस्य सादाब, प्रतिनिधि सासंद रमेश पोखरियाल निशंक सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग